29-10-26 VNS PG-6 EDITORIAL.qxd 28-10-2026 19:18 Page 1

लूटकी खुली छूट

सर्वोच्च न्यायालयने कैंसरकी दवाओंपर भारी मुनाफेकी खुली लूटपर कड़ी टिप्पणी करते हुए एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर पूरा तंत्र दवा निर्माता कम्पनियोंकी क्यों मदद कर रहा है? कैंसरकी दवाओंपर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और रिटेल विक्रेताओंको मिलने वाली कीमत (रिटेलर प्राइस) में भारी अन्तरपर मंगलवारको न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहताकी पीठने जो कड़ी टिप्पणी है वह सरकार और दवा निर्माता कम्पनियोंको कड़ा सन्देश भी है। पीठका यह भी कहना महत्वपूर्ण है कि दवाओंके मूल्य निर्धारणमें इतना बड़ा अन्तर होनेके बाद भी पूरा तंत्र दवा निर्माताओंकी सहायतामें क्यों सक्रिय है? यह लूटकी खुली छूट जैसा है। साथ ही यह भी सवाल उत्पन्न होता है कि क्या निर्माताओंको मनमानी करनेकी छूट दी जानी चाहिए? यह मुद्दा आम नागरिकों और गरीब मरीजोंसे जुड़ा है। यह केवल व्यापारका मामला नहीं है। पीठने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की भूमिकाको भी कटघेरेमें खड़ा कर दिया है और कहा है कि एनपीपीए पूरी तरहसे निष्क्रिय निकाय लगता है। पीठका यह भी कहना है कि ११ हजार रुपयेमें मिलने वाला कीमोथैरिपीका इंजेक्शन एक लाख ३० हजार रुपयेमें कैसे बेचा जा रहा है और मूल्योंके बीच भारी अन्तरका धन कहां जा रहा है? वस्तुत: सर्वोच्च न्यायालयकी कड़ी टिप्पणीको केवल दवा निर्माता कम्पनियों या निजी अस्पतालोंकी आलोचनाके रूपमें देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह मामला भारतकी स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजोंके अधिकारसे सीधे जुड़ा है। सर्वोच्च न्यायालयने दवाओंकी खरीद और बिक्री मूल्योंमें इस भारी अन्तरको अत्यन्त गम्भीर माना है और कहा है कि मरीजोंको इस प्रकारकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? सर्वोच्च न्यायालयकी चिन्ता केवल यह नहीं है कि कोई कम्पनी अधिक मुआवजा कमा रही है। मूल प्रश्न यह है कि क्या जीवनरक्षक दवाओंके बाजारमें मरीजकी मजबूरीका फायदा उठाया जा सकता है? कैंसर जैसी बीमारीमें मरीज और परिवारके पास दवा खरीदनेके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है और वह कीमतपर मोलभाव करनेकी स्थितिमें भी नहीं होता है। ऐसेमें बाजारकी सामान्य मांग-आपूर्ति वाली अवधारणा कमजोर पड़ जाती है। इस पूरे प्रकरणमें अलग-अलग स्तरपर शुल्क लिया जा रहा है। अस्पताल और डाक्टरोंकी मनमानी कमाई और उपहार तथा अन्य सुविधाएं देनेकी संस्कृतिसे भी दवाओंके मूल्य बढ़ जा रहे हैं। इसे कैसे रोका जाय इसपर सरकारको सोचना होगा। निगरानी तंत्रको भी मजबूत करना होगा तभी मूल्योंमें कमी आ सकती है।

वायु प्रदूषणका दंश

वायु प्रदूषण पृथ्वीके जीवधारियोंके अस्तित्वके लिए बड़े खतरेका संकेत हैं। इसे नियंत्रित करनेके लिए वैश्विक मंचोंसे बातें तो बड़ी-बड़ी की जाती हैं और इसके निदानके लिए रास्ते भी सुझाये जाते हैं लेकिन यह महज कागजोंतक सिमटकर रह जाता है। कोई भी देश इस समस्याको गम्भीरतासे नहीं लेता। यह गम्भीर चिन्ताका विषय है। भारतके शहरोंको स्वच्छ हवा देनेके लिए पिछले सात सालोंमें १२ हजार करोड़ रुपयेसे अधिक खर्च किये गये, इसके बावजूद देशके ९० प्रतिशत शहरोंमें प्रदूषणका स्तर निर्धारित मानकके अनुरूप नहीं हो सका। दिल्लीकी स्थिति सर्वाधिक चिन्ताजनक है। आंकड़ोंपर गौर करें तो वर्ष २०१६ से २०२५ तक राजधानीका वार्षिक औसत स्तर किसी भी साल राष्ट्रीय मानकोंके अनुरूप नहीं रहा। सेण्टर फार रिसर्च आन एनर्जी एण्ड क्लीन एयरके स्वतंत्र विश्लेषणके अनुसार जनवरी २०१९ में शुरू किये गये इस कार्यक्रममें सात साल बाद भी प्रदूषण नियंत्रणकी तस्वीर सन्तोषजनक नहीं है। खास बात यह है कि प्रदूषित हवाका दुष्प्रभाव जीवधारियोंपर तो पड़ ही रहा है, कृषि उत्पादपर भी इसका व्यापक प्रभाव दिख रहा है जो देशके विकास और अर्थव्यवस्थाके लिए शुभ संकेत नहीं है। हवा क्यों प्रदूषित हो रही है, इसके कारण और निवारणके बारेमें सोचना और इसके लिए सख्त कदम उठाना होगा। प्रदूषणपर आक्सफैमकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसके अनुसार दुनियाके सबसे अमीर करीब ८० लाख लोग न केवल प्रदूषण फैलानेमें आगे हैं, बल्कि इससे होने वाली प्राकृतिक आपदाओंसे दोहरा मुनाफा कमानेमें भी आगे हैं। ये धनकुबेर दुनियाकी सबसे गरीब ३५० करोड़ आबादीके मुकाबले ज्यादा कार्बन प्रदूषण फैलाते हैं। इन बेहद अमीर लोगोंका ऐसे कारोबारमें भारी निवेश है, जो पर्यावरणको नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपदाओंसे राहत, बचाव, मरम्मत और पुनर्निर्माणसे जुड़े कारोबारमें भारी निवेश कर दो गुना मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे लोगोंपर अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर दबाव बनानेकी जरूरत है, तभी वायुकी गुणवत्ता सुधारी जा सकती है।

लोक संवाद

पर्यावरण का संरक्षण जरूरी

महोदय,-दुनिया आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषणकी गम्भीर चुनौतीका सामना कर रही है। पर्यावरण संरक्षणकी जिम्मेदारी पूरी मानवता की है, लेकिन प्रदूषणके मुद्देपर विकासशील देशोंको अक्सर कठघरेमें खड़ा किया जाता है। विकसित देश भूल जाते हैं कि उन्होंने दशकोंतक संसाधनोंका अधिकतम दोहन कर मजबूत आर्थिक ढांचा खड़ा किया है, जिसकी पर्यावरणीय कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। यदि प्रदूषणकी जिम्मेदारी तय करनी है तो ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनको भी ध्यानमें रखना होगा। कार्बन टैक्स और पर्यावरण संबंधी प्रतिबंधोंके नामपर विकासशील देशोंके विकासको बाधित करना न्यायसंगत नहीं है। पर्यावरण संरक्षण व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका हथियार नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोगका माध्यम होना चाहिए। विकसित देशोंको अपना फर्ज समझना होगा। **-महेश कुमार, वाया ईमेल।**

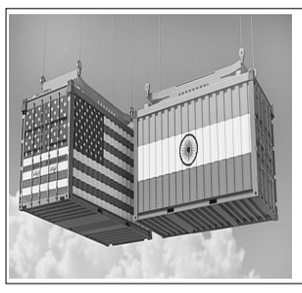
व्यापार समझौतेकी सम्भावना

हालमें ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पने कहा कि भारत और अमेरिका एक नये व्यापार समझौतेको अंतिम रूप देनेके बेहद करीब हैं। डोनाल्ड ट्रम्पने स्पष्ट किया कि दोनों देश समझौता करनेके इच्छुक हैं और यह नया सौदा पिछले सभी द्विपक्षीय समझौतोंसे काफी अलग होगा।

❐ डा. जयंतीलाल भंडारी

हालमें ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरेपर आये। मार्कोने २० से २२ अक्तूबरके बीच भारत दौरेके दौरान भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर और अन्य शीर्ष नेताओंके साथ व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा सहयोगके मुद्दोंपर विस्तृत चर्चा की। रुबियोने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के जामनगर संयंत्रका दौरा किया और भारतकी इस अनूठी रिफायनिंग क्षमताकी सराहना की। रुबियोने यह भी कहा कि भारत-अमेरिकी व्यापार वार्ता अब अंतिम और तकनीकी स्तरपर पहुंच चुकी है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दशकोंमें वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक मानचित्रपर भारत और अमेरिकाके संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक साझेदारीके रूपमें उभरे थे, लेकिन वर्तमान परिदृश्यमें ये संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी नयी आर्थिक नीतियों, संरक्षणवादी दृष्टिकोण और सख्त टैरिफ रणनीतिके कारण एक चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील मोड़पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज भारतके समक्ष एक तरफ अमेरिकी बाजारमें अपने मजबूत निर्यातको सुरक्षित रखनेकी चुनौती है तो दूसरी तरफ रूससे रियायती दरोंपर अपनी ऊर्जा जरूरतोंकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनेका रणनीतिक संतुलन साधनेका दबाव है। इस खींचतानके बीच हालिया अमेरिकी नीतिगत फैसले, वीजा नियमोंमें अत्यधिक सख्ती, जेनेरिक दवाओंपर प्रस्तावित शुल्ककी चुनौतियोंके बावजूद अमेरिकाके राष्ट्रपति ट्रम्प और विदेश मंत्री रुबियोकी हालिया सकारात्मक टिप्पणियोंसे भारत और अमेरिकाके बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) एक नयी पटकथाके साथ उभरते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि १९९१ के आर्थिक उदारीकरणके बादसे लेकर २०१६ तक भारत और अमेरिकाके बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधोंमें एक प्रभावी दौर देखनेको मिला। वर्ष २००० में दोनों देशोंके बीच वस्तुओं एवं सेवाओंका द्विपक्षीय व्यापार लगभग छह गुना बढ़कर अभूतपूर्व स्तरपर पहुंच गया। इस दौरान अमेरिकी बाजारमें भारतीय आईटी सेवाओं, फार्मास्युटिकल उत्पादों, कपड़ों और रत्नोंकी मांगमें जबरदस्त इजाफा हुआ, जिससे भारतकी आर्थिक साख वैश्विक स्तरपर स्थापित हुई। इस आर्थिक प्रगतिको २००८ के ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते और २०१६ में भारतको मिले मेजर डिफेंस पार्टनरके दर्जेसे गहरा रणनीतिक बल मिला। रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकियोंके हस्तांतरणके नये द्वार खुलनेके साथ-साथ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कम्पनियों जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रोने अमेरिकी अर्थव्यवस्थामें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान एच१बी वीजा नीतिने भारतीय कुशल पेशेवरोंको अमेरिकामें कार्य करने और वैश्विक पहचान बनानेके पर्याप्त अवसर प्रदान किये। निवेशके दृष्टिकोणसे भी यह दौर बेहद समृद्ध रहा, जहां २००० से २०१६ के बीच माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जीई, आईबीएम और बोइंग जैसी शीर्ष अमेरिकी कम्पनियोंने भारतके तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्रोंमें भारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई किया। साथ ही भारतीय कम्पनियोंने भी अमेरिकी बाजारमें अपनी उपस्थिति दर्ज करायी।

ट्रम्प कालमें शुरू हुई संरक्षणवादी नीतियों, टैरिफ और वीजा पाबंदियोंसे ठीक पहलेतक दोनों देशोंके आर्थिक रिश्ते मुक्त और रणनीतिक सहयोगकी मजबूत नींवपर लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसेमें अब अमेरिकासे व्यापार समझौतेकी संभावनाओंका सुकूनदेह परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। हालमें १७ अक्तूबरको अमेरिकी प्रशासन द्वारा लींडसे ग्राहम अधिनियमके तहत रूसी तेल खरीददारोंपर सौ प्रतिशत टैरिफ लगानेके कठोर फैसलेको ६० दिनोंके लिए स्थगित करना भारतीय अर्थव्यवस्थाके लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। मध्य-पूर्वके तनाव और यूक्रेन-रूस संघर्षसे उपजे ऊर्जा संकटके बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियोने भारतकी ऊर्जा जरूरतों और स्रोतोंके विविधीकरणकी सराहना की है। रूससे प्रतिस्पर्धी दरोंपर कच्चा तेल खरीदनेकी इस छूटसे भारतमें ईंधनकी लागत नियंत्रित रहेगी और घरेलू बाजारमें महंगीका दबाव कम होगा। इसके साथ ही इस फैसलेने टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम-गहन क्षेत्रोंके भारतीय निर्यातकों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अल्पकालिक अनिश्चिततासे बचाकर अंतरराष्ट्रीय ऑर्डरोंका प्रवाह बनाये रखनेमें मदद की है। नि:संदेह तेल टैरिफपर ६० दिनोंकी राहतके बावजूद, आव्रजन और वीजा नियमोंमें सख्तीके कारण भारतीय आईटी पेशेवरों, कारपोरेट जगत और चिकित्सा विशेषज्ञोंपर संकट गहराता जा रहा है। एच१बी वीजापर लगाये गये एक लाख डालरके अतिरिक्त शुल्कको एक वर्षके लिए बढ़ाने और जांच प्रक्रियाको बेहद सख्त करनेसे बड़ी भारतीय आईटी कम्पनियोंके पंजीकरणमें ९२ प्रतिशततककी भारी गिरावट दर्ज की गयी है, जबकि कुल मंजूर एच१बी वीजामें भारतीयोंकी हिस्सेदारी लगभग ७१ प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त नौकरी छूटनेके बाद मिलने वाले ६० दिनोंके वैधानिक ग्रेस पीरियडको खत्म करनेका नया प्रस्ताव भारतीय पेशेवरोंके लिए गम्भीर संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि नौकरी समाप्त होते ही उनका कानूनी गैर-आप्रवासी दर्जा खत्म हो जायगा और उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़कर पुन: आवेदन करनेकी बाध्यता होगी। ऐसेमें अमेरिकासे आर्थिक अनिश्चितता और संरक्षणवादके इस दौरमें भारतको केवल रक्षात्मक रुख अपनानेके बजाय अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितोंकी सुरक्षाके लिए एक दीर्घकालिक और बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। अमेरिका और यूरोपीय संघपर अत्यधिक निर्भरता कम करनेके लिए लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्वके गैर-पारम्परिक बाजारोंमें भारतीय उत्पादोंकी पैठ बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओंके साथ लंबित मुक्त व्यापार समझौतोंको तेजीसे अंतिम रूप देना होगा।



भारत और अमेरिकाके बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार समझौतेकी वार्ताके तहत भारतको सहयोग और व्यापारिक प्रतिस्पर्धाके बीच एक संतुलित और दृढ़ रुख अपनाना होगा। भारतको कृषि, डेयरी और एमएसएमई जैसे संवेदनशील क्षेत्रोंमें राष्ट्रीय हितोंकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि इन क्षेत्रोंसे भारतकी विशाल आबादीकी आजीविका जुड़ी हुई है। इसके साथ ही औषधियों, वस्त्र, हस्तशिल्प और जेम्स एंड ज्वेलरीपर टैरिफ दरोंको शून्य या न्यूनतम स्तरपर लानेके लिए भारतको कड़ा मोलभाव करना होगा, ताकि भारतीय निर्यातकोंको अमेरिकी बाजारमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता रहे।

घरेलू स्तरपर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओंका विस्तार करना होगा और सेवा क्षेत्रको कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर तथा उच्च प्रौद्योगिकीकी दिशामें अपग्रेड करना होगा, ताकि अमेरिकी नीतियोंके झटकोंका प्रभाव न्यूनतम किया जा सके। भारत और अमेरिकाके बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार समझौतेकी वार्ताके तहत भारतको सहयोग और व्यापारिक प्रतिस्पर्धाके बीच एक संतुलित और दृढ़ रुख अपनाना होगा। भारतको कृषि, डेयरी और एमएसएमई जैसे संवेदनशील क्षेत्रोंमें अपने राष्ट्रीय हितोंकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि इन क्षेत्रोंसे भारतकी विशाल आबादीकी आजीविका जुड़ी हुई है। इसके साथ ही औषधियों, वस्त्र, हस्तशिल्प और जेम्स एंड ज्वेलरीपर अमेरिकी टैरिफ दरोंको शून्य या न्यूनतम स्तरपर लानेके लिए भारतको कड़ा मोलभाव करना होगा, ताकि भारतीय निर्यातकोंको अमेरिकी बाजारमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता रहे। अंतत: अमेरिका द्वारा मिली ६० दिनोंकी यह राहत भले ही अस्थायी और अल्पकालिक हो, लेकिन यह भारतके लिए महज एक सांकेतिक छूट नहीं है। यह ६० दिनोंका समय भारतको नये सिरेसे संजोनेका एक प्रभावी अवसर प्रदान करता है।

साइबर सुरक्षाकी जानकारी आवश्यक

डिजिटल इंडियाने देशमें सुविधाओंके नये रास्ते खोले हैं। लेकिन इसकी सफलताका आकलन केवल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, मोबाइल ऐप या आनलाइन लेन-देनकी बढ़ती संख्यासे नहीं किया जा सकता। असली सफलता तब होगी जब सामान्य नागरिकको छोटेसे छोटे कामके लिए बार-बार सरकारी कार्यालय न जाना पड़े।

❐ रमेश धवाला

भारतमें पिछले कुछ वर्षोंमें डिजिटल तकनीकने हमारे दैनिक जीवनको काफी बदल दिया है। कभी बिजलीका बिल जमा करने, पैसे भेजने या सरकारी प्रमाण-पत्र बनवानेके लिए लम्बी कतारोंमें खड़ा होना पड़ता था। आज इनमेंसे अनेक काम मोबाइल फोनसे किये जा सकते हैं। वर्ष २०१५ में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके नेतृत्वमें शुरू हुए डिजिटल इंडिया अभियानने देशमें डिजिटल सेवाओंको बढ़ानेकी दिशामें महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हालांकि इस बदलावके साथ एक सवाल भी जुड़ा है कि क्या इन सुविधाओंका लाभ समाजके हर वर्गतक समान रूपसे पहुंच रहा है। डिजिटल इंडियाका सबसे बड़ा उद्देश्य सरकारी सेवाओंको आम नागरिकके लिए सरल और सुलभ बनाना रहा है। आज अनेक प्रमाण-पत्रोंके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। डिजिलॉकर जैसी सुविधाओंने जरूरी दस्तावेजोंको सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़नेपर उपलब्ध करानेका रास्ता आसान किया है। इससे लोगोंके समय और पैसेकी बचत हुई है। लेकिन कई बार वेबसाइट ठीकसे काम नहीं करती या आवेदन लम्बे समयतक लम्बित रहते हैं।

ऐसी स्थितिमें नागरिकको वही परेशानी उठानी पड़ती है जिससे बचानेके लिए आनलाइन व्यवस्था बनायी गयी थी। इसलिए तकनीकके विस्तारके साथ प्रशासनिक जवाबदेही भी जरूरी है। डिजिटल भुगतानने भी भारतीय समाजमें बड़ा बदलाव लाया है। आज छोटे दुकानदार, सब्जी विक्रेता और रेहड़ी लगाने वाले भी यूपीआईसे भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। इससे नकद पैसे रखनेकी जरूरत कम हुई है और लेन-देन अधिक सुविधाजनक बना है। हालांकि इसके साथ आनलाइन धोखाधड़ीकी घटनाओंने नयी चिन्ताएं पैदा की हैं। फर्जी संदेश, अनजान लिंक और ओटीपीके माध्यमसे ठगीके मामले बताते हैं कि डिजिटल सुविधाओंके साथ लोगोंको साइबर सुरक्षाकी जानकारी देना भी आवश्यक है। सरकारी योजनाओंका लाभ सीधे लोगोंके बैंक खातोंमें पहुंचानेकी व्यवस्था भी महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरणसे बिचौलियोंकी भूमिका कम करनेमें सहायता मिली है। फिर भी कुछ लोगोंको आधार, बैंक खाते या तकनीकी समस्याओंके कारण कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रोंमें बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे नागरिकोंके लिए ये प्रक्रियाएं आसान नहीं हैं। ऐसी स्थितिमें सहायता केन्द्रों और वैकल्पिक व्यवस्थाओंकी भूमिका बढ़ जाती है। किसी पात्र व्यक्तिको केवल तकनीकी समस्याके कारण सरकारी सहायतासे वंचित नहीं होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्यके क्षेत्रमें भी डिजिटल तकनीककी उपयोगिता बढ़ी है। ऑनलाइन कक्षाओं, अध्ययन सामग्री और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमोंने विद्यार्थियोंके लिए नये अवसर पैदा किये हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और डिजिटल रिकॉर्डसे मरीजोंको सुविधा मिल सकती है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओंका उद्देश्य पात्र परिवारोंको उपचारके खर्चसे राहत देना है। लेकिन यह भी समझना होगा कि डिजिटल कार्ड, ऑनलाइन पाठ्यक्रम या प्रमाण-पत्र अपने आप बेहतर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओंकी गारंटी नहीं हैं। इनके लिए अच्छे संस्थान, प्रशिक्षित कर्मचारी और आवश्यक संसाधन भी चाहिए। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यमें डिजिटल सुविधाओंका महत्व और अधिक है। यहां अनेक गांव जिला मुख्यालयों और सरकारी कार्यालयोंसे काफी दूर स्थित हैं।

किसी छोटेसे कामके लिए भी लोगोंको लम्बी यात्रा करनी पड़ती है। हिमसेवा और लोकमित्र केन्द्रों जैसी व्यवस्थाएं इस दूरीको कम करनेमें सहायक हो सकती हैं। यदि गांवमें ही प्रमाण-पत्र, बिल भुगतान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों तो लोगोंको बड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेशके पर्यटन और बागवानी क्षेत्रोंमें भी डिजिटल तकनीक नयी संभावनाएं लेकर आयी है। छोटे होटल और होमस्टे संचालक ऑनलाइन बुकिंगसे पर्यटकोंतक पहुंच रहे हैं। बागवान मौसम, मंडी भाव और बाजारकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनके लिए बेहतर निर्णय लेना सम्भव होता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रोंमें कमजोर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेटकी समस्या अब भी गम्भीर है। कई दूरदराजके गांवोंमें इंटरनेटकी गति इतनी कम होती है कि सामान्य ऑनलाइन आवेदन भरना भी मुश्किल हो जाता है। डिजिटल भारतकी एक बड़ी चुनौती समाजमें मौजूद डिजिटल असमानता है। शहरोंमें रहने वाले शिक्षित और आर्थिक रूपसे सक्षम लोगोंके लिए तकनीकका उपयोग अपेक्षाकृत आसान है। इसके विपरीत गरीब परिवारों, बुजुर्गों और ग्रामीण नागरिकोंके सामने अनेक कठिनाइयां हैं। स्मार्टफोनकी कीमत, इंटरनेटका खर्च, भाषाकी समस्या और तकनीकी जानकारीका अभाव उन्हें पीछे छोड़ सकता है। इसलिए डिजिटल सेवाओंको केवल अंग्रेजी या कठिन प्रशासनिक भाषातक सीमित नहीं रखना चाहिए। हिन्दी और स्थानीय भाषाओंमें सरल निर्देश उपलब्ध कराना भी जरूरी है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नागरिकोंकी निजी जानकारीकी सुरक्षाका है। आज बैंक, पहचान और स्वास्थ्यसे जुड़ी बहुत-सी जानकारी डिजिटल माध्यमोंमें दर्ज होती है।

इसका गलत उपयोग लोगोंके लिए गम्भीर परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए सरकार और संबंधित संस्थाओंको डेटा सुरक्षा, शिकायत निवारण और साइबर जागरूकतापर लगातार ध्यान देना होगा। लोगोंका विश्वास बनाये रखना किसी भी डिजिटल व्यवस्थाकी सफलताके लिए आवश्यक है। निस्संदेह डिजिटल इंडियाने देशमें सुविधाओंके नये रास्ते खोले हैं। लेकिन इसकी सफलताका आकलन केवल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन लेन-देनकी बढ़ती संख्यासे नहीं किया जा सकता। असली सफलता तब होगी जब किसी दूरस्थ गांवका बुजुर्ग बिना परेशानी अपनी पेंशन प्राप्त कर सके, कोई विद्यार्थी संसाधनोंके अभावमें शिक्षासे वंचित न रहे और सामान्य नागरिकको छोटेसे छोटे कामके लिए बार-बार सरकारी कार्यालय न जाना पड़े। तकनीक तभी सार्थक है जब वह लोगोंका जीवन आसान बनाये।



मासानां कार्तिक: श्रेष्ठ:

❐ अनिरुद्ध जोशी

कार्तिक मास भारतीय संस्कृतिका सबसे पवित्र और ऊर्जावान समय माना जाता है। चातुर्मासका अंतिम पड़ाव होनेके कारण शास्त्रोंमें इसे सभी महीनोंमें शिरोमणि 'मासानां कार्तिक: श्रेष्ठ:' की संज्ञा दी गयी है। यह वही पावन समय है जब चार महीनेकी योगनिद्राके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं और सृष्टिका संचालन पुन: संभालते हैं, जिससे इस माहमें किये गये हर धार्मिक कार्यका फल अनन्त गुना हो जाता है। इस पावन मासको दामोदर मास भी कहा जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीकी आराधना जीवनको सुख, समृद्धि और धन-धान्यसे सराबोर कर देती है। कार्तिक और तुलसी जीका नाता बेहद गहरा है। इस पूरे महीने तुलसीके पौधेके पास दीप जलाना और तुलसी विवाहका आयोजन करना घरमें असीम शुभता लाता है। पद्म एवं स्कन्द पुराणके अनुसार, यह महीना जीवनके चारों पुरुषार्थों-धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको साधनेका समय है। इस दौरान तड़के पवित्र नदियोंमें डुबकी लगानेसे मन और आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। करवा चौथका अटूट प्रेम, दीपावलीकी जगमगाहट, गोवर्धन पूजाकी श्रद्धा, भाई दूजका स्नेह और छठ पूजाका महासंकल्प-ये सभी बड़े पर्व इसी एक महीनेको खुशियोंसे भर देते हैं। कार्तिक पूर्णिमाके दिन जब भगवान शिवने असुर तारकासुरका संहार किया था, तब देवताओंने खुश होकर दीप जलाये थे। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान और दीपदानका अभूतपूर्व महत्व है। कार्तिक मासकी मुख्य पौराणिक कथाएं हैं, जैसे धनवंतरी जयंती कथा, लक्ष्मी पूजा कथा, नरक चतुर्दशीकी कथा, यम और यमुनाकी कथा, गोवर्धन पूजाकी कथा आदि, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व तारकासुरके वधकी कथाका माना जाता है। पौराणिक कथाके अनुसार, तारकासुर नामके एक शक्तिशाली दैत्यने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जीसे वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिवके पुत्रके हाथों ही हो सकती है। वरदान मिलनेके बाद तारकासुरने तीनों लोकोंमें अत्याचार मचाना शुरू कर दिया और देवताओंको स्वर्गसे निष्कासित कर दिया। तारकासुरके तीन पुत्र थे-ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन्होंने ब्रह्मा जीकी तपस्या करके तीन अजेय नगरोंका निर्माण कराया, जिन्हें त्रिपुर कहा गया। ये नगर सोने, चांदी और लोहेके बने थे और अंतरिक्षमें उड़ सकते थे। वरदान यह था कि तीनों नगर १००० वर्षोंमें केवल एक बार ही एक सीधी रेखामें आयंगे और उन्हें केवल एक ही तीरसे नष्ट किया जा सकता था। दैत्योंके अत्याचारसे पीड़ित होकर सभी देवता भगवान शिवकी शरणमें पहुंचे। शिव जीने देवताओंकी रक्षाका वचन दिया। कार्तिक पूर्णिमाके दिन जब तीनों नगर (त्रिपुर) एक सीधी रेखामें आये, तब भगवान शिवने अपने दिव्य धनुष और एक ही बाणसे तीनों नगरोंको भस्म कर दिया और तारकासुर एवं उसके पुत्रोंका अंत कर दिया।

अखण्ड सौभाग्य प्रदाता चौथव्रतोत्सव

❐ रमेश सर्राफ धमोरा

भारत एक धर्म प्रधान देश हैं। यहां सालके सभी दिनोंका महत्व होता है तथा सालका हर दिन पवित्र माना जाता है। भारतमें करवा चौथ हिन्दुओंका एक प्रमुख त्योहार है। यह कार्तिक मासकी कृष्ण पक्षकी चतुर्थीको मनाया जाता है। यह व्रत सुबह सूर्योदयसे पहले करीब ४ बजेके बाद शुरू होकर रातमें चन्द्रमा दर्शनके बाद सम्पूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियोंसे लेकर आधुनिक महिलाएं करवा चौथका व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साहके साथ रखती हैं। यह व्रत लगातार १२ अथवा १६ वर्षतक हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होनेके पश्चात इस व्रतका उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवनभर इस व्रतको कर सकती हैं। करवा चौथका व्रत हर साल महिलाओं द्वारा अपने पतियोंके लिए किया जाता हैं और यह न केवल एक त्योहार है, बल्कि यह पति-पत्नीके पवित्र रिश्तोंका पर्व है। कहनेको तो करवा चौथका त्योहार एक व्रत है लेकिन यह नारी शक्ति और उसकी क्षमताओंका सवश्रेष्ठ उदहारण हैं। क्योंकि नारी अपने दृढ़ संकल्पसे यमराजसे भी अपने पतिके प्राण ले आती हैं तो फिर वह क्या नहीं कर सकती हैं। आजके नये जमानेमें भी हमारे देशमें महिलाएं हर वर्ष करवा चौथका व्रत पहलेकी तरह पूरी निष्ठा एवं भावनासे मनाती है। सूर्योदयसे लेकर चंद्रोदयतक पत्नियां अपने पतिके प्रति पूरे प्रेम और सम्मानके साथ ये सभी रस्में निभाती हैं। यह त्योहार हर साल कार्तिक मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्थीको मनाया जाता है।

शास्त्रोंके अनुसार पतिकी दीर्घायु एवं अखण्ड सौभाग्यकी प्राप्तिके लिए इस दिन भालचन्द्र गणेश जीकी पूजा-अर्चना की जाती है। करवा चौथमें दिनभर उपवास रखकर रातमें चन्द्रमाको अर्ध्य देनेके उपरान्त ही भोजन करनेका विधान है। वर्तमान समयमें करवा चौथव्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवारमें प्रचलित प्रथाके अनुसार ही मनाती हैं। लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चन्द्रोदयकी प्रतीक्षा करती हैं। सायंकाल चंद्रमाके उदित हो जानेपर चंद्रमाका पूजन कर अर्ध्य प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियों एवं पतिके माता-पिताको भोजन करायें। भोजनके पश्चात ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिणा दें।

कार्तिक कृष्ण पक्षकी चन्द्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात् उस चतुर्थीकी रात्रिको जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है। उस दिन प्रात: स्नान करके अपने पतिकी आयु, आरोग्य, सौभाग्यका संकल्प लेकर दिनभर निराहार रहें। उस दिन भगवान शिव-पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमाका पूजन करें। शुद्ध घीमें आटेको सेंककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर नैवेद्य हेतु लड्डू बनायें। काली मिट्टीमें शक्करकी चासनी मिलाकर उस मिट्टीसे तैयार किये गये मिट्टीके अथवा तांबेके बने हुए अपनी सामर्थ्य अनुसार १० अथवा १३ करवे रखें। करवा चौथके बारेमें व्रत करने वाली महिलाएं कहानी सुनती है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वतपर गये। इधर द्रोपदी बहुत परेशान थीं। उनकी कोई खबर न मिलनेपर उन्होंने कृष्ण भगवानका ध्यान किया और अपनी चिन्ता व्यक्त की। कृष्ण भगवानने कहा बहना इसी तरहका प्रश्न एक बार माता पार्वतीने शंकरजीसे किया था। पू